

पहले मुख्य समाचार।

- घाना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान कम्पैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा-यह पुरस्कार पाना अत्यंत गर्व और सम्मान की बात।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग व लॉजिस्टिक्स क्लस्टर-यूपी आईएमएलसी की करेंगे लॉन्चिंग।
- प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हो रही मानसूनी बारिश से कई नदियों का जल स्तर बढ़ा, वाराणसी जिले में चौरासी घाटों का आपसी सम्पर्क टूटा, बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में बढ़ाई गई सतर्कता।
- लखनऊ में दस साल बाद जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल घाना में वहां के सर्वोच्च राजकीय सम्मान कम्पैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाना उनके लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि वह इस सम्मान को एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को भारत के युवाओं की आकांक्षाओं, उनके उज्ज्वल भविष्य, देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता व परम्पराओं और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री के पांच देशों की यात्रा के पहले चरण में कल घाना की राजधानी अक्रा पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पिछले तीस वर्ष में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग व लॉजिस्टिक्स क्लस्टर-यूपी आईएमएलसी की लॉन्चिंग करेंगे। इसके तहत प्रदेश के एक्सप्रेस वेज के किनारे विकसित किए जा रहे सप्ताईस नोड्स की लॉन्चिंग होगी। इन नोड्स को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण-यूपीडा द्वारा विकसित किया जा रहा है। इनके विकास से रोजगार सृजन की संभावना बनेगी और प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनामी बनाने में मदद मिलेगी। इन नोड्स का विकास प्रमुख तौर पर गंगा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर किया जा रहा है।

श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अगले चार वर्षों में कर्मचारियों और नियोजकों को एक लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए पांच वर्षीय कार्यक्रम तैयार किया है।

ये स्कीम प्रधानमंत्री जी की इम्प्लाइमेंट इनसेंटीव नीति का नतीजा है। देश के युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए पांच साल का कार्यक्रम मोदी जी ने बनाया था। उसके तहत ईएलआई स्कीम लाई गई है। ईएलआई स्कीम के द्वारा देश में जो युथ नया जॉब में आता है, तो उसको एक साल में दो किस्त में सात हजार पांच सौ-सात हजार पांच सौ रुपया डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में डाला जाएगा।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्स ने कहा है कि कोविड के टीकों और युवाओं की अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई संबंध नहीं है। देश के दो प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों के व्यापक अध्ययनों में पुष्टि हुई है कि भारत में इस्तेमाल हुए कोविड के टीके सुरक्षित और प्रभावी रहे हैं। दोनों संस्थाओं ने दो अध्ययन किए हैं। पहले अध्ययन में लोगों की आयु अठारह और पैंतालिस वर्ष के बीच थी। एक रिपोर्ट-

पहले अध्ययन का परिणाम यह दर्शाता है कि कोविड-19 टीकाकरण से लोगों में अचानक मृत्यु का जोखिम नहीं बढ़ता है। वहीं दूसरा अध्ययन जो एम्स नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। उसके प्रारंभिक विश्लेषण यह पता चलता है कि हार्टअटैक या मायोकार्डियल इनफार्क्शन इस आयु वर्ग में अचानक मृत्यु का प्रमुख कारण बना हुआ है। यह अध्ययन भारत में युवा वयस्कों में अचानक होने वाली मृत्यु के बारे में अधिक व्यापक समझ प्रदान करते हैं। अध्ययनों में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के जोखिम में अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं की भूमिका हो सकती है। वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने दोहराया है कोविड टीकाकरण को अचानक मौतों से जोड़ने वाले बयान झूठे और भ्रामक हैं। आनंद कुमार के साथ, आकाशवाणी समाचार के लिए आदर्श दिल्ली।

प्रदेश की पंचायतों को सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग और आईआईटी कानपुर के बीच कल एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर उपस्थित पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस एमओयू के तहत पंचायतों को डिजिटल दक्षता के लिए आईआईटी कानपुर द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं प्रदेश में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आईआईटी कानपुर और आईबीएम के बीच भी कल एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और डाटा का इस्तेमाल कर वायु प्रदूषण का समाधान निकालना है। इसमें आईबीएम की प्रयोगशाला की मदद ली जाएगी।

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हो रही मानसूनी बारिश से कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कल बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से सिर्फ आधा मीटर नीचे बह रही थी। वाराणसी में गंगा उफान पर है जिसकी वजह से 84 घाटों का सम्पर्क आपस में टूट गया है। साथ ही घाटों के पास बने मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। खतरे को देखते हुए गंगा नदी में छोटी नावों के संचालन पर रोक लगा दी गयी है। वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कल बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बाढ़ से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

जो बाढ़ चौकियों की स्थापना करनी होती है वो सारी तैयारियाँ हो गई हैं। एनडीआरएफ और जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को डिप्लॉय करना होता है उसकी भी प्लानिंग कर ली गई है तो सभी प्रकार से जो बाढ़ की तैयारियाँ होती है समग्र रूप से उसको लेकर तैयारियाँ हैं और लगातार जलस्तर पर भी सतर्क दृष्टि रखा जा रहा है।

प्रयागराज में भी गंगा और यमुना में नाव सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अयोध्या और गोंडा में सरयू तथा घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गोंडा की जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि सभी बाढ़ चौकियां अलर्ट पर हैं। इस बीच, मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में छह जुलाई तक कहीं कहीं भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल से छह जुलाई तक यही स्थिति रहेगी।

लखनऊ में दस साल बाद जमीनों के सर्किल रेट में पंद्रह से लेकर पचीस प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की तैयारी है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट—

नये सर्किल रेट में कृषि भूमि पर 15, व्यावसायिक पर 25, और बहुमंजिला भवनों पर 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। दुकान, कार्यालय और गोदामों पर औसतन 20 फीसदी की वृद्धि प्रस्तावित है। लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी ने कहा कि ये सर्किल रेट बाजार मूल्य में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए तय किए गए हैं। प्रशासन की ओर से इस संबंध में लोगों से दावे और आपत्तियां मांगी गई हैं। नई दरों से संबंधित सुझाव और आपत्तियां दो से 17 जुलाई के बीच सुबह 10 से पांच बजे तक सभी उप निबंधक कार्यालयों, सहायक महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय में दी जा सकती है। इन आपत्तियों का निस्तारण 27 जुलाई तक होगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से शैलेन्द्र शर्मा।

प्रदेश के खादी और ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान की उपस्थिति में कल लखनऊ में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. पीयूष सिंह को प्रदेश की एमएसएमई, खादी, हथकरघा एवं रेशम उद्योगों से संबंधित नीतियों और योजनाओं से अवगत कराया गया। इस मौके पर श्री सचान ने कहा कि राज्य में करीब एक करोड़ एमएसएमई ईकाईयां काम कर रही हैं।

हापुड़ जिले के हाफिजपुर थानाक्षेत्र के पड़ाव इलाके में कल देर रात एक कैंटर और बाइक की टक्कर में बाइक सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब एक युवक चार नाबालिग बच्चों के साथ पास के एक गांव से लौट रहा था कि पड़ाव इलाके में कैंटर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दिया। वहीं उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में कल ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से कांवड़ यात्रियों को ले जा रहा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें तीन कांवड़ यात्रियों की मृत्यु हो गई, जबकि अट्ठारह अन्य घायल हो गए।
